

Volume 6 | Issue 3 | July-Sept. | 2018 | ISSN- 2347-5145

IJRRSS

**International Journal of
Reviews and Research in Social Sciences**

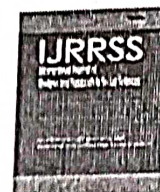
**An International Peer- reviewed
Journal of Humanities and Social Sciences**

ISSN 2347-5145 (Print)
2454-2687 (Online)

Available online at
www.anvpublication.org

Vol. 06| Issue-03|
July- September 2018

International Journal of
Reviews and Research in Social Sciences



RESEARCH ARTICLE

भारत में खाद्य सुरक्षा का आर्थिक विश्लेषण

डॉ. प्रति कुशवाहा

सहा.प्राध्यापक (वाणिज्य), सिन्धू कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)

*Corresponding Author E-mail:

ABSTRACT:

खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है सभी लोगों को सक्रिय और स्वस्थ जीवन बिताने के लिये कभी भी भोजन का अभाव न होने देना। सर्वप्रथम ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दै सिल्व्वा ने अपने यहाँ खाद्य सुरक्षा का कानून लागू किया था। लूला के प्रयोग की सफलता ने सारी दुनिया के लिये सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल देने का काम किया। हमारे देश के लिये भी खाद्यान्न सुरक्षा बेहद जरूरी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना खाये जिंदा नहीं रह सकता है। हालांकि भारत ने 35 वर्ष पहले ही इस मामले में आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली, इसके बावजूद आज भी देश में 35 प्रतिशत जनसंख्या खाद्यान्न के मामले में असुरक्षित है। देश में हरितक्रांति के फलस्वरूप उत्पादन कई गुणा बढ़ा है। इसके बावजूद जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है उनके अनुरूप खाद्यान्न का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि देश में हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है और रोज लगभग 10 से 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं अप्रैल 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक गोष्ठी में कहा था, कि "लोकतंत्र और भूख साथ-साथ नहीं चल सकते हैं"। भूख और कुपोषण पर 'हंगामा' रिपोर्ट जारी करते हुये प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि "हमारी जी.डी.पी. में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद देश में कुपोषण का स्तर अस्वीकार्य रूप से ऊँचा है यह बड़े शर्म की बात है"।

KEYWORDS: खाद्य सुरक्षा, ग्लोबल हंगर इण्डेक्स, खाद्यान्न उत्पादन, खाद्य असुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली

प्रस्तावना:-

मानव की तीन मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, कपड़ा और मकान में भोजन सबसे पहली और प्रमुख आवश्यकता है। पर्याप्त भोजन पाना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। विश्व की बुनियादी आवश्यकताओं में खाद्य संसाधन प्रमुख है। आज हमारे सामने ऐसी स्थिति है कि जहाँ एक तरफ कुछ लोगों को खाने के लिये न के बराबर भोजन मिल पाता है। वहीं दूसरी तरफ अन्य लोगों के पास जरूरत से ज्यादा भोजन है।

भारत की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में औद्योगिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। और कृषि क्षेत्र पर नगण्य ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर उन बातों को नियंत्रित करने की जरूरत है जो औद्योगिक विकास को बढ़ाने के क्रम में कृषि क्षेत्र को क्षति पहुँचाते हैं। खाने के लिये हमें अन्न चाहिये न कि इस्पात और सोना इसलिये खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये सभी वांछित प्रयास किये जाने चाहिये।

Received on 07.09.2018

Modified on 19.09.2018

Accepted on 28.09.2018

© A&V Publications All right reserved

Int. J. Rev. and Res. Social Sci. 2018; 6(3):305-310.

OI: